SHIVAJI UNIVERSITY KOLHAPUR

Golden Jubilee Year 2019-20 of

Department of Political Science

&

Shivaji University Political Science Association

Conference Prociding of Two Days National Seminar

&

37th Maharashtra Political Science & Public Administration Conference

"Contemporary Issues in Political Science"

10th & 11th January 2020

Navjyot

ISSN - 2277 - 8063

International Interdisciplinary research Journal

(Humanities, Social Sciences, languages, Commerce & Management)

Scanned by CamScanner

43	डिजिटल समाजाच्या संदर्भात बदलते राजकारण	डॉ. नंदाजी सातपुते	176-177
44	भारतीय नागरिकत्व नावनोंदणी संघर्ष आणि : वास्तव	डॉ.गणेश गिरी	178-181
45	एक राष्ट्र एक चुनाव कि उपलब्धयाँ और चुनोतियाँ	डॉ.प्रा लक्षटे रत्नाकर बाबुराव	182-184
46	कलम ३७० : घटनात्मक तरतुदी	डॉ.सुधीर वाडेकर	185-189
47	लोकशाहीसमोर झुंडशाहीचे आव्हान	दत्तात्रय भानुदास जाधव	190-194
48	एक देश, एक निवडणुक!	प्रा.माधव डॉ. चोले	195-198
49	भारतातील आघाडीच्या राजकारणाची वाटचाल व विश्लेषण	प्राशरद बाबुराव सोनवणे	199-203
50	भारतीय लोकशाहीला नक्षलवादी चळवळीचे आव्हान	प्रा.डॉ.कैलाश बद्रीनाथ मांटे	204-205
51	महाराष्ट्राच्या राजकारणातील नेतृत्वांचे बदलते प्रवाह	नवनाथ वि. नागरे	206-207
52	भारतातील सहभागात्मक लोकशाही प्रक्रिया	प्रा.डॉ.आर.बी.वनारसे	208-216
53	डिजिटल समाजाच्या संदर्भात बदलते राजकारण	प्रा.चैतन्य कांबळे प्रा.सुजाता पाटील	217-218
54	भारताची लोकशाही खरोखरच घसरत आहे का?	डॉ.बाळ कांबळे सहा.प्रा.प्राजक्ता ठुबे	219-223
	POLITICAL THOUGHT AND ITS CONTEMPORARY RELEVANCE		
55	Non Brahmin Feminist Perspective : Study Of Contributions Of Mahatma Phule And Tarabai Shinde	Mrs. Neha Nitin Wadekar,	224-228
56	Role Of Satyagrah In Democracy	Prof.Promod J. Patil	229-233
57	Gandhi And Gloalization	Dr.Rajendra S. Korde	334-241
58	Relevance Of Gandhian Philosophy In The 21st Century	Sunil Kavade Firoj Shaikh	242- 246-
59	Relevance Of Gandhian And Post Gandhian Thoughts	Dr. Suresh M. Devare	247-251
60	Gandhian Principles The 21st Century	Mr. P. S. Auti	252-254
61	Democratic Thought Of Mahatma Gandhi	Dr. Avinash V.Salve	255-257
62	The Concept Of Neo-Gandhian Thoughts About Sarvodaya	DR. R. K. KALE	258-261
63	Relevance Of Mahatma Gandhi's Ideology In The Present Scenario	Prof. Sanjay M. Mohade	262-264
64	The Relevance Of Gandhian Thought	Dr.Mahadev Gavhane Prof. Dnyaneshwar Bansode	265-267
65	Contribution Of Gandhian Thoughts To Rural Development	Dr.Santosh S. Kolhe	268-270
66	Relevance Of Gandhian And Post Gandhian Thought	Dr. A. D. Jadhao	271-273

Scanned by CamScanner

एक राष्ट्र एक चुनाव कि उपलब्धयॉं और चुनोतियॉं

प्रा. डॉ. लक्षटे रत्नाकर बाबुराव
स्नातक एवं स्नातकोत्तर राजनितीविज्ञान विभागाध्यक्ष देगलूर महाविद्यालय, देगलूर

.....

प्रस्तावना

चुनाव लोकतांत्रिक शासनप्रणालियों में जान फुंकने का काम करते है। लोकतंत्र को जिवित रखने में चुनाव कि अहम भुमिका होती है । इसिलिए सभी लोकतांत्रिक देशो में पारदर्षी और नि:पक्ष चुनाव पर जोर दिया जाता है । इसके हेतु चुनाव प्रक्रिया समेत अन्य चिजों में सुधार कि प्रक्रिया को अपनाते हैं। चुनावि सुधार से चुनाव दोषमुक्त और सुचारु लोकतंत्र का निर्माण होता है। भारत में □जादि के बाद से अबतक चुनावी सुधार के अनेक प्रयास किये है। जो काफी हदतक सफल हुये है।

वर्तमान भारतीय राजनिती में लोकतंत्र औऱ चुनाव में सुधार करने हेतू अनेक विचारों का दौर छिडा है। जिसमें "एक राष्ट्र एक चुनाव " एक महत्वपूर्ण विषय है। एक राष्ट्र एक चुनाव इस विषय पर राजनितिक दलों का विभाजन दो गुटों में हु□ है । एक गुट इसे लोकतंत्र के सुधार एंव सुदृढता का महत्वपुर्ण कदम मानता है, तो दुसरा गुट इसे असंवैधानिक बताता है। प्रस्तावित शोधलेख में एक राष्ट्र एक चुनाव से सम्बन्धित उपलब्धियॉं और चुनौतिंयों का विश्लेषण एक राष्ट्र एक चुनाव इस विषय पर सोचविचार करने के प्राथमिक अवस्था से प्राप्त विषयों के मद्देनजर रखते हुये किया है।

यह शोधलेख एक राष्ट्र एक चुनाव की उपलब्धियॉं और चुनौतियों को उजागर करने हेतू से लिखा है। यह लेख वर्तमान भारतीय और राज्य चुनावी प्रक्रिया में होनेवाले अलोकतांत्रिक ,असंवैधानिक ,चुनावी गठजोड एवं सत्ता का खिंचाव □दि के सुक्ष्म विश्लेषण पर □धारित है।

पार्श्वभूमी

वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार □ने के बाद एक राष्ट्र एक चुनाव कि चर्चा हो रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है ? एक राष्ट्र एक चुनाव की □वश्यकता क्यों है ? एक राष्ट्र एक चुनाव की उपलब्धियॉं और चुनौतियॉं क्या है ? ऐसे अन्य विषयों पर पिछले छह साल से देश में चर्चा हो रही है । एक राष्ट्र एक चुनाव में निम्न बातें सम्मिलित होगी।

1. लोकसभा चुनान के साथ सभी राज्यों की चुनाव प्रक्रिया पुर्ण करना।
2. लोकसभा चुनाव के साथ कुछ राज्यों के विधिमंडल के चुनाव करवाना।

एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया और विचार भारत में पुर्णता नया नही है। □जादि के बाद 1952,1957,1962 और 1967 तक लोकसभा एवं विधिमंडल के चुनाव एक साथ हुए थे। 1967 के बाद अनेक राज्यों के विधिमंडल अनेक कारणों से समाप्त कर मध्यावधी चुनाव कि प्रक्रिया को अपनाया, जिससे एक राष्ट्र एक चुनाव कि प्रक्रिया खंडित हुई।

एक राष्ट्र एक चुनाव अन्तराष्ट्रिय स्थिती

एक राष्ट्र एक चुनाव से सम्बन्धित अन्तराष्ट्रिय परिदृष्य के बारे में विचार करने से यह ज्ञात होता है कि, विश्व के अनेक देशों में एक हि बार चुनाव होते है। जिसमें स्विडन, इंडोनेशिया, साऊथा □फ्रिका, जर्मनी, स्पेन, हंगेरी, बेल्जियम, पोलंड,स्लोव्हेनिया,अल्बेनिया, □दि देश सम्मीलीत है। जिसमें कुछ युरोप तो कुछ अफ्रिकी खंड के है। भारत कि तुलना में इन सभी देशों की भौगौलिक,सामाजिक,राजनितीक,□र्थिक,और संस्कृतिक स्थिती में अधिक अंतर है। लेकिन देशहित,जनहित,लोककल्याण कि भावना से प्रेरित होकर वहॉं के राजनितीक दल तथा राजनेताओं ने एकही समय चुनाव के विचार एवं प्रक्रिया को अपनाया है।

एक राष्ट्र एक चुनाव की उपलब्धियॉं –

एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार राजनिती के चक्रव्युह में फंसा है। राजनितिक दल एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार कि उलब्धियोंको राजनिती की अंग से समज रहे है। एक राष्ट्र एक चुनाव उपलब्धियों का विश्लेषण सामाजिक,□र्थिक एवं राजनितीक द्रष्टी से कर सकते है।

सामाजिक उपलब्धियॉं –

वर्तमान भारतिय लोकतंत्र के सुचारु रुप से चलाने हेतू सामाजिक शांती कि □वश्यकता है। निरंतर होनेवाले चुनावों ने इस सामाजिक शांती को मानो भंग कर दिया है । चुनाव चाहे वो स्थानिय निकाय का हो, या संसदिय, वो

Scanned by CamScanner

ISSN 2277-8063

जात,धर्म,भाषा,प्रदेश,लिंग इन सभी सामाजिक तथ्यों का विचार उनमें होता है। व्यक्ती की सामाजिक सोंच बिगडती है। असामाजिक तत्वों को सहारा मिलता है। सामाजिक स्वास्थ को बिगाडकर अपना राजनितीक लाभ पुर्ण करने वाली शक्ती का बोलबाला होता है। एक राष्ट्र एक चुनाव से जाती,धर्म,वंश,भाषा आदि के आधार पर होनेवाला चुनवी प्रचार,चुनावी नारों का प्रयोग पुर्णता बंद नही होगा ,पर चुनाव कम होने से उसका प्रयोग आज कि तुलना में 60 प्रतिशत कम होगा । चुनाव के समय काम कर रहे असामाजिक शक्ति पर गौर कर उनकोही प्रसारित कर [illegible]आरपी बढाने की इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यमों कि गंदि सोच पर पाबंदी आएगी। राजनितीक नेताओं की भडकाऊ बयानबाजी, चुनाव एक ही समय होने से एकबार हि होगी । निरंतर चुनाव में युवावर्गों को जिस प्रकार भडकाया जाता है, वह कम होगा । युवा अपने भविष्य के बारें में सोचेंगे । राजनितीक दल और नेता के फर्जी चुनावी प्रक्रिया में सम्मिलित होनेवाला युवा अपने परीवार,माता-पिता,भविष्य के बारें में सोचकर प्रगती की राह पर चलेगा । राष्ट्रहित,जनहित के बारें में सोचने वोलों की संख्या बढेगी । आदि से भी ज्यादा सामजिक उपलब्धियॉं है ।

आर्थिक उपलब्धियॉं –

निरंतर होनेवाले चुनाव से एकही बार होने वाला चुनाव अच्छा है । यह विचार आर्थिक बचत के कारण समर्थनिय है। हमारे प्रधानमंत्री,राष्ट्रपती,निती आयोग समेत इसके सभी समर्थकोंने इसकी पुष्टी कि है । उससे शासन, राजनितीक दल, राजनेता तथा जनता , या ए कहे चुनाव प्रक्रिया से सम्बन्धित सभी वर्गों की आर्थिक बचत होगी । भारत में हर साल औसता पॉंच राज्यों के चुनाव होते है । निरंतर चुनाव से काले पैसे का प्रमाण बढता है । यह एक सत्य है । निरंतर होनेवोले चुनावों में काले पैसे को सफेद किया जाता है । एक हि चुनाव हो जाचगें तो काले पैसौ पर रोक लगेगी और अर्थव्यवस्था की गती सुधरेगी । एकही बार चुनाव होने से अर्थिक विकास तिव्र गती से होगा । जनहित और जनकल्याणकारी योजनाओं को क्रियन्वयन करने हेतू राष्ट्र के पास पैसौ की उपलब्धी होगी । चुनाओं में होनेवाला भ्रष्ट्राचार कम होगा। सत्ता के गठजोड में होनेवाली पैसें की आवाजाही कम होगी । पैसों से राजनितिक लोकप्रतिनिधी का दल बदलना कम होगा । निरंतर होने वाले चुनावों से अपने निजी कामों से भ[illegible]ने वाले लोगों की संख्या कम होगी । विकसित राष्ट्र बननेकी दिशा में पहल होगी । पायाभुत सुविधाओ का निर्माण अधिक होगा । निरंतर चुनाव बढती जनसंख्या पर नियंत्रण के विचार को नकारते हैं । जो राष्ट्रहित में नहीं होगा । एकहिबार होनेवाला चुनाव और जनसंख्या नियंत्रण का पारस्पारिक संबंध है ।

र[illegible]निनितिक उपलब्धियॉं-

निरंनतर होनेवाले चुनाव तुलना में एकही बार होनेवाले चुनाव से राजनितिक उपलब्धियॉं अधिक है । एकही बार होनेवाले चुनावो से लोकतंत्र मजबूत एवं स्थिर बनेगा । लोगों में राष्ट्रहित कि भावना का स्थर बढेगा । भारतीय राजनिती की दर्जा में सुधार होगा । अलोकतांत्रिक, असंविधानिक तरिकेसे होनेवाली राजनिती पर रोक लगेगी । लोगों का विश्वासघात नही होगा । फर्जी चुनावी नारेबाजी , वायदों से राजनितीक दलों का छु[illegible]कारा होगा। राजनितीक दलों के चुनावी कार्योक्रमोमें और कार्य करने की पध्दती में सुधार आएगा । सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनेगी । मनुष्यबल का सही ढंग से लोककल्याण हेतू इस्तेमाल होगा । प्रशासन के स्तर पर सुधार होगा । शासन और प्रशासन की कार्य गती में सकारात्मक बदलाव आयेंगे । उनकी क्षमता में विकास होगा । शासन की सभी यंत्रणा पारदर्शी और सही ढंग से काम करेगी । निरंतर आनेवाली बाधा से प्रशासनिक यंत्रणा को छु[illegible]कारा मिलेगा । विकास कार्य कि गती बढेगी । निहित समय में जनहित से सम्बन्धित कार्य पुर्ण होगें । प्रशासनिक भ्रष्टाचार कम होगा ।

इन सभी उपलब्धियों को दखकर हमें एक राष्ट्र एक चुनाव कि प्रक्रिया का क्रियान्वयन करना चाहिए ऐसा लगता है । लेकिन एक राष्ट्र एक चुनाव कि प्रक्रिया से कुछ दोषों का भी निर्माण होता है । या यह कह सकते है की, कुछ सामजिक, आर्थिक, एवं राजनितीक चुनौतियों का भी निर्माण इसके क्रियान्वयन से होगा।

एक राष्ट्र एक चुनाव से बेरोजगारी की समस्या बढेगी । छो[illegible]व्यापारियों को परेशानी को सामना करना पडेगा । लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के विषय अलग-अलग होते है, लेकिन एकहि चुनाव होने से राष्ट्रिय राजनितीक दल स्थानिक विषयों की बजाय राष्ट्रिय विषयों को अधिक महत्व देंगे । प्रादेशिक राजकिय दलों को अनेक परेशानियोंका सामना करना पडेगा । एकही समय चुनाव होने से प्रादेशिक दलों की तुलना में राष्ट्रिय दलों का महत्व बढेगा । प्रादेशिक दलों के लिए एकही समय चुनाव पोषक नहीं है । चुनावी खर्च, चुनावी रणनिती आदि के कारण राजनितीक दलों में प्रादेशिक दल इसे मान्यता नहीं देंगे।

Scanned by CamScanner

वर्तमान में अनेक राजनितीक दल मतपत्रिका के साह्यतासे चुनाव कराने की मांग करते है। अगर ऐसा होता है तो चुनावों के नतिजे आने में देर होगी। वर्तमान भारतीय लोकतांत्रीक शासन व्यवस्था में □कही समय चुनाव लेना नामुकिन है। क्योंकी इससे सभी राज्यों में राजनितीक दलों को स्पष्ट बहुमत मिलेगा इसकी कोई ग्यारंटी नहीं है। स्पष्ट बहुमत नहीं मितलेगा तो सरकार कैसे बनेगी ? आदि सवाल और संवैधानिक समस्याओं का निर्माण हो जायगा। संयुक्त सरकार के युग में पांच साल के अंदर हि सरकार गीर जाती है। ऐसे समय में वहां फिर से चुनाव कि आवश्यकता निर्माण होती है। □के राष्ट्र □के चुनाव की व्यवस्था को कार्यान्वित करने हेतू आवश्यक सरकारी यंत्रणा, कर्मचारी, संसाधन और मशिनों की आपूर्ती की बाधाओं का निर्माण होगा। इन सभी समस्याओ की ओर दृष्टिगोचर करने से □के राष्ट्र □के चुनाव बडी ही कठिण प्रक्रिया लगती है।

एक राष्ट्र एक चुनाव हेतू आवश्यक सुझाव -

□के राष्ट्र □के चुनाव कि व्यवस्था को क्रियान्वित कराने हेतू हमें भारतीय संविधान के निम्न धारओं में सुधार करने होंगे। जैसे कि धारा 83 जो सरकार के कार्यकाल से सम्बन्धित है। धारा 85 जो संसद को निष्कासित करने के राष्ट्रपती के अधिकार से सम्बन्धित है। धारा 172,174 जो राज्य विधिमंडल से सम्बन्धित है। धारा 356 जो राज्यो में राष्ट्रपती शासन काल से सम्बन्धित है। इसके आलावा लोकप्रतीनीधी कायदा 1951 में भी बदलाव करना होगा। इन सभी संविधानिक धाराओं में सुधार करने से □के राष्ट्र □के चुनाव कि प्रक्रिया सहज बनेगी। इसके लि□सभी राजनेता और राजनितीम दलों में राजनितीक इच्छा का होना जरुरी है। अपना राजनितीक स्वार्थ के लाभ से उपर उठकर सभी ने राष्ट्रहित और जनकल्याण का विचार करने से ही यह संभव होगा।

आजादी के बाद अबतक भारत के राजनेता और राजनितीक दलों ने अनेक राष्ट्रहित, जनहित से जुडे विषयोंपर □कमत बनाकर ,अपने स्वार्थोको पिछेकर उन्हें अमल में लाया है। जैसे - 73,74 संविधान सुधार, माहिती अधिकार आदि. इसितरह □के राष्ट्र □के चुनाव के बारें में भी सभी राजनितीक दल अपने स्वार्थों को हटाकर और □के होकर इसे व्यवहार में लायेंगे , ऐसी आशा हम कर सकते है। इस विषय पर अधिकाधिक विचारमंथन, चर्चा और जागृती करनी होगी। सभी सामजिक, आर्थिक □वं राजनितीक मंचोपर इस विषय के बारे में जनहित और राष्ट्रहित को सामने रखकर चर्चा हो, ना की राजनितीक लाभ, स्वार्थ, राजनितिकरण को महत्व देकर।

सारांश

□के राष्ट्र □के चुनाव का विचार वर्तमान भरतीय राजनिती का महत्वपुर्ण विषय है। इस विषयपर पिछले छह साल से सभी स्तर पर चर्चा हो रही है। निरंतर होनेवाले चुनाव से □कही समय होनेवाले चुनाव की प्रक्रीया अधिक हितावह है। लेकिन इसके क्रियान्वयन में अनेक संविधानिक, लोकतांत्रिक समस्यायें है। यह □के आव्हानात्मत प्रक्रिया है। इस विषयपर सबसे अधिक विचारमंथन, चर्चा कि आवश्यकता है। इस चर्चा में सभी का सहभाग जरूरी है। चर्चा लोकतांत्रिक, पारदर्शी, राष्ट्रवादी विचारधारा से हो, ना की राजनितीकरण से प्रेरित हो। □के राष्ट्र □के चुनाव का विचार सामाजिक, आर्थिक □वं राजनितीक सुधार का □के मार्ग है।

संदर्भ –

1. Report of Nitti Ayoag.
2. भारत में निर्वाचन व्यवस्था चुनौतीयाँ □वं सम्भावनायें – आर.□म.आढा (□बीडी पब्लिकेशन जयपुर भारत 2008)
3. लोकतंत्र को पतन भविष्य का पुनर्निर्माण – फिलीप कॉटलर(□म□जीइ 2017)
4. भारतीय निवडणुक प्रणाली स्थित्यंतर व आव्हाने - डॉ तुषार निवृत्ती निकाळजे (हरित पब्लिकेशन 2016)
5. भारत में मतदान व्यवहार का मापन – संजय कुमार ,प्रविण रॉय SAGE 2013
6. भारतीय युवा और चुनावी राजनीती – संपादन संजच कुमार SAGE 2014

Scanned by CamScanner